कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का समय बर्बाद कर रही है - भजन लाल

मुख्यमंत्री ने कहा, जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा था तब कांग्रेस विधायक कहाँ थे

जयपुर, 10 सितंबर। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को उस वक्त भारी हंगामा हुआ, जब सदन में लगे अतिरिक्त कैमरों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जासूसी के आरोप ल गाए। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कैमरों को जासूसी उपकरण बताया और कहा कि यह विपक्ष की निजता में दखल और लोकतंत्र का उल्लंघन है।

कैमरा विवाद पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रदेश की 8 करोड़ जनता की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं, वह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का समय बर्बाद कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, कि विपक्ष का यह व्यवहार न केवल सदन की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि जनता के साथ विश्वासघात भी है। जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा था, तब कांग्रेस के विधायक कहां थे? न राहत कार्यों में सहयोग दिया, न पीड़ितों के पास गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब सदन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चल रहा है, तब विपक्ष कैमरों की संख्या गिनने में व्यस्त है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सदन में लगे कैमरे सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हैं, उनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की कोई सुविधा नहीं है।

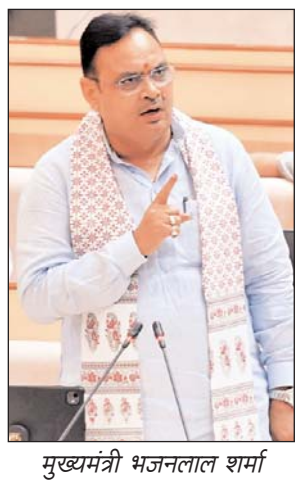

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- **कांग्रेस विधायकों ने कैमरों को "निगरानी टूल" बताया और आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इससे विपक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखना चाहता है।**

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कैमरे अपग्रेड किए गए, तब उसकी जानकारी विपक्ष को क्यों नहीं दी गई? उन्होंने पूछा कि जब सदन स्थगित होता है, तब भी कैमरे क्यों चालू रहते हैं? क्या इनसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होता है और यह किसके आदेश पर हो रहा है?

कांग्रेस विधायकों ने कैमरों को "निगरानी टूल" बताते हुए आरोप लगाया कि इससे सत्ता पक्ष, विपक्ष की गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है, जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली में अस्वीकार्य है।

मॉरीशस के प्र.मंत्री का वाराणसी में भव्य स्वागत

वाराणसी, 10 सितंबर। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम बुधवार शाम तीन दिवसीय यात्रा पर काशी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सड़क मार्ग द्वारा वे होटल ताज पहुंचे। रास्ते में छह स्थानों पर स्वागत प्वाइंट बनाए गए थे, जहां काशीवासियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।

हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत किया। गिलट बाजार में मॉरीशस के प्रधानमंत्री के स्वागत में आजमगढ़ के कलाकारों लिल्ली घोड़ी धोबिया नृत्य पेश किए तो स्कूली बच्चों ने विभिन्न रूपों में दोनों देशों के फ्लैग के साथ खड़े होकर स्वागत किए।

जयपुर व उदयपुर के पर्यटक काठमांडू व पोखरा में फंसे

पोखरा शहर में पर्यटकों के सामने भीड़ ने एक होटल को फूंक दिया

उदयपुर, 10 सितम्बर। नेपाल में 8 सितंबर से हो रहे हिंसात्मक आंदोलन में 4 हजार से ज्यादा राजस्थानी फंसे हुए हैं। इन लोगों ने सरकार से भी मदद मांगी है। इनमें से अधिकतर पर्यटक हैं। इनमें 700 पर्यटक जयपुर के और 35 पर्यटक उदयपुर जिले के भी हैं।

इनमें उदयपुर के एक भाजपा नेता भी हैं, जो पोखरा शहर के एक होटल में परिवार के साथ फंसे हैं। उदयपुर के भाजपा नेता अनिल सिंघल ने बताया कि वे काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर दूर पोखरा शहर में फंसे हैं। हमारे सामने आगजनी की घटनाएं हुईं। एक होटल को आग के हवाले कर दिया गया। हम दूतावास के संपर्क में हैं।

- **काठमांडू में फंसे यात्रियों ने बताया कि भारतीय दूतावास के निर्देश पर वे सब होटल के अंदर ही हैं। वहां जयपुर और भीलवाड़ा के लोग भी हैं।**

इधर काठमांडू में उदयपुर से गया 31 लोगों का एक और ग्रुप फंसा हुआ है। एयरपोर्ट बंद होने से वे लोग निकल नहीं पा रहे हैं। उदयपुर से गए ग्रुप के मेंबर भगवतीलाल मेनारिया ने बताया कि वे स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। मेनारिया ने बताया कि वे भारतीय दूतावास से संपर्क में हैं और वहां से उन्हें यही निर्देश दिए गए हैं कि वे अभी जहां हैं, वहीं रुकें और इंतजार करें। ऐसे में वे सब अभी होटल के अंदर ही हैं और स्थितियों के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहां पर जयपुर और भीलवाड़ा के लोग भी हैं।

सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही चिंता दोहराई। एक अलग दलील में सिंघवी ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर दोहरी वोटिंग के आरोपों को लेकर जल्दबाज़ी में कार्रवाई न करे, क्योंकि यह बनावटी मामला है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहला अवसर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत की आंतरिक संवैधानिक तनातनी को क्षेत्रीय घटनाओं से सीधे जोड़ा है। जिस समय पर यह टिप्पणी की गई है, वो समय भी अहम है। ऐसे समय पर, जबकि कई राज्य विधानसभाएँ राज्यपालों पर विधेयक रोकने की शिकायत कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी विपक्षी दलों को मज़बूत कर सकती है और केन्द्र को घेर सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेपाल का ज़िक्र मोदी सरकार के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि अगर संस्थागत गतिरोध पर काबू न पाया गया तो इसके, सामान्य राजनीतिक विवादों से कहीं अधिक अस्थिर करने वाले परिणाम हो सकते हैं।

पोलैण्ड ने रुस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"कोअलिशन ऑफ़ द विलिंग" नाम का समूह बनाया है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश शामिल हैं, जिन्होंने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के तौर पर वहाँ सैनिक तैनात करने का प्रस्ताव दिया है। इसके जवाब में रूस ने चेतावनी दी और सुनियोजित ढंग से रात के हमलों को और तेज़ कर दिया। रविवार को हुए ताज़ा हमले में पुतिन के हवाई हमलों ने सरकारी इमारतों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे आम लोगों को भारी नुक़सान हुआ।

पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति को भी चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने बार-बार पुतिन को गंभीरता से बातचीत की मेज़ पर आने और हमले कम करने की समय सीमा दी थी। तथापि, डॉनल्ड ट्रंप रुस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने तथा बातचीत की मेज पर लाने के लिए और कड़े प्रतिबंध लगाने से बचते रहे हैं।

भारत पर सैकैण्डरी सैंक्शन्स लगाने के अलावा, ट्रंप ने कभी चीन या यूरोपीय देशों पर वैसी पाबंदियाँ लगाने की हिम्मत नहीं की, जो अब तक रूस का तेल और ऊर्जा खरीदते रहे हैं। चीन ने भी ट्रंप की धमकियों को नाकाम कर दिया और ज़रूरी सामग्रियों की आपूर्ति रोकने की धमकी दी।

अब ट्रंप यूरोपीय देशों से गुज़ारिश कर रहे हैं कि वे चीन और भारत पर खुद ही सैकेण्डरी सैंक्शन्स लगाएँ, वह भी और कठोर, क्योंकि ये दोनों रूस का तेल खरीदते रहे हैं। रूस से तेल ख़रीदने वाले कई अन्य देशों के ख़िलाफ़ ट्रंप द्वारा मज़बूत कदम नहीं उठाने से पुतिन और भी निडर हो गए हैं।

इस बीच, चीन किनारे बैठा यह पूरा संघर्ष देख रहा है और साफ़ तौर पर रूस का समर्थन कर रहा है। किनारे खड़े कुछ लोग भारत से मध्यस्थता की अपील कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा भारत के साथ किए गए रुखे व्यवहार को देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम है।

अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिका से जुड़े माने जाते हैं। इन सब तथ्यों को देखकर ऐसा लगता है कि यह पूरा घटनाक्रम "एक सुव्यवस्थित शासन परिवर्तन की कोशिश" का हिस्सा है।

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सारण को सशर्त जमानत

जयपुर, 10 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में उदयपुर के बेकरिया थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपी भूपेन्द्र सारण को जमानत पर सशर्त रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश भूपेन्द्र सारण की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह मुकदमे की ट्रायल पूरी होने तक हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। वहीं, संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का एक रजिस्टर संधारित करेंगे और उसकी उपस्थिति रिपोर्ट बिना देरी संबंधित कोर्ट में पेश करेंगे। अदालत ने संबंधित निचली अदालत को कहा है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से पहले, थानाधिकारी के जरिए जमानती का पता और संपर्क नंबर का सत्यापन करेंगे।

बीकानेर में कांग्रेस नेता के घर पर लॉरेंस गैंग का हमला

कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता से फोन पर रोहित गोदारा के नाम से 5 करोड़ रु. रंगदारी मांगी गई थी

बीकानेर, 10 सितम्बर। यहां कांग्रेस नेता धनपत चायल और व्यापारी सुखदेव चायल के घर पर बदमाशों ने सात राउंड फायरिंग की। इससे घर में लगे कांच टूट गए। दरवाजे, दीवार, खिड़कियों पर गोलियों के निशान भी मिले हैं। धनपत और सुखदेव सगे भाई हैं।

जानकारी के अनुसार, बुधवार अलसुबह चार बजे हुई इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने ली है। उसने घटना की जिमेवारी ली और सोशल मीडिया पर लिखा, अब सीधे सीने पर गोली मारेंगे। सादुलगंज क्षेत्र में बुधवार सुबह हुई घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोलियों के निशान और अन्य साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी फुटेज में हेलमैट पहने दो युवक बाइक पर सवार दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में फायरिंग की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है। हैरी बॉक्सर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि इस हमले की जिम्मेदारी मैं हैरी बॉक्सर और सुंदर हंसी, हम दोनों भाई लेते हैं। ये फायरिंग हमने करवाई है। इसको हमारे फोन की रिंग सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए हमने ये छोटी सी वॉर्निंग दी है। आगे टाइम रहते लाइन पर आ जाएगा ये, वर्ना आगे अब सीधे सीने में गोली मारेंगे। सुखदेव चायल के भाई और कांग्रेस नेता धनपत चायल ने बताया कि कुछ दिन पहले एक फोन आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। धनपत के मुताबिक, कॉलर ने धमकी दी कि उसे, उनकी और उनके भाई की हर गतिविधि की जानकारी है और रंगदारी न देने पर जान से मारने की चेतावनी दी थी। धनपत चायल बीकानेर में यूथ कांग्रेस के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष पद पर रहे हैं।

- **लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर ने अपने सोशल मीडिया अकाउन्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली।**

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करेगा। इसके तहत हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय के कानून-व्यवस्था कार्यालय में स्थापित विशेष सेल से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0141-2740832 और 0141-2741807 जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, व्हाट्सएप नंबर 9784942702 पर भी सहायता के लिए संदेश भेजा जा सकता है।

नकल कर सुपरवाईज़र बनी महिला गिरफ्तार

जयपुर,10 सितंबर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने कार्रवाई करते हुए, सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कर सुपरवाईजर बनी आरोपित महिला को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसओजी की टीम ने सुपरवाईजर (महिला अधिकारिता) भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कर सुपरवाइजर बनी आरोपित महिला मंजू कुमारी निवासी मुक्ता प्रसाद नगर जिला बीकानेर हाल सुपरवाइजर महिला अधिकारिता बज्जू जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया है। आरोपित मंजू कुमारी ने सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करवाने वाली गैंग की मदद ली थी और ब्लूटूथ डिवाइस से प्रश्न पत्र हल किया। आरोपित को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। आरोपित महिला मंजू कुमारी से उक्त भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह के संबंध में पूछताछ की जा रही है। एसओजी द्वारा अब तक उक्त प्रकरण में 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

क्या नेपाल की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कई मंत्रियों के आवासों में आग लगा दी। काठमांडू समेत कई अन्य क्षेत्रों में आगजनी और लूटपाट जैसी घटनाएं हुईं। ओली के इस्तीफे के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि इस हिमालयी राष्ट्र की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा।

एक एनजीओ "हामी नेपाल" से जुड़े सुदीप गुरुङ जो इस आंदोलन के नेता है, ने नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया। कार्की को पहले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के चलते महाभियोग का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह प्रयास बाद में छोड़ दिया गया।

हालांकि, उनके नाम पर रवि लामिछाने की पार्टी 'राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टी' (आरएसपी) सहित अन्य दलों की सहमति भी लेनी होगी।

सूत्रों के अनुसार, जस्टिस कार्की इस पद की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, हालांकि वार्ताएं अभी चल रही हैं। भद्रकाली, काठमांडू स्थित जंगी अड्डा (सेना मुख्यालय) में बुधवार को जैनरेशन ज़ैड प्रदर्शनकारियों और उनके सहयोगियों की बैठक हुई, जिसमें अंतरिम सरकार के संभावित नेताओं पर चर्चा की गई। काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह अर्थात रैपर से नेता बने 35 वर्षीय बालेन भी प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने जैनरेशन ज़ैड नेताओं के फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया।

- **जैनरेशन ज़ैड आंदोलन के नेता सेना के मुख्यालय जंगी अड्डा में अतंरिम सरकार के नेतृत्व के बारे में विचार - विमर्श कर रहे हैं।**

सुमना श्रेष्ठा युवा वर्ग में लोकप्रिय नेता ने आरएसपी से अपने जुड़ाव का हवाला देते हुए यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। धरान के मेयर हर्का सम्पर्क ने भी नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए अपनी तत्परता जाहिर की।

सागर धकाल- जिन्होंने संघीय चुनावों में शेर बहादुर देउबा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, ने भी कहा कि वह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल धनगड़ी में फंसे हुए हैं।

कुलमान घिसिंग- नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक, जो कल की प्रेस विज्ञप्ति में मेंटॉर के रूप में शामिल थे, एक मार्गदर्शक भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्र बिमोचन तिमल्सेना जो एक लोकप्रिय यूट्यूबर और पेशे से वकील हैं, उन्होंने कहा कि यदि कोई उपलब्ध नहीं हुआ, तो वह नेतृत्व करने को तैयार हैं। इस बीच, सेना ने काठमांडू में गुरुवार शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर रखा है।

दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

- **सुप्रीम कोर्ट ने नीरज और सीबीआई निरीक्षक विनोद कुमार पांडे पर मुकदमा चलाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।**
- **यह मामला उस समय का है जब नीरज सीबीआई के संयुक्त निदेशक थे। आरोप है कि उन्होंने और निरीक्षक पांडे ने एक आई आर एस के भाई को धमकाया व गाली गलौच की थी।**

नयी दिल्ली, 10 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त नीरज कुमार और एक अन्य अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को मुहर लगा दी।

न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। यह मामला उस समय का है जअ नीरज सीबीआई संयुक्त निदेशक थे, उन पर और तत्कालीन सीबीआई निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय पर एक आईआरएस अधिकारी के भाई विजय अग्रवाल को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करने का का आरोप है। उन पर इसी मामले में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने सहित दुर्व्यवहार और धमकी देने के आरोप हैं।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2006 के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि कथित अपराध वर्ष 2000 में किया गया था और आज तक मामले की जांच की अनुमति नहीं दी गई है। पीठ ने कहा कि मामले की जांच का आदेश देने में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं। यदि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो मुकदमा दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है। कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी,पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज़ कर दी।

क्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2016 में महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबन्दी कर दी। भले ही वह नीति विवादास्पद रही हो तथा आलोचकों ने शराब के अवैध व्यापार और राजस्व की हानि के आरोप लगाये हों, लेकिन राजनैतिक रूप से नीतीश कुमार ने एक ऐसे राजनेता की प्रतिष्ठा अर्जित कर ली, जो महिलाओं की ओर विशेष ध्यान देता है।

छात्राओं के लिए साइकिल योजना, स्कूल यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति और स्टाइपेन्ड, और बाद में "जीविका" स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाएं, जिनसे आज 1.4 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, ने नीतीश सरकार को ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। हर नीति का संदेश एक ही था, राज्य आपकी बात ध्यान से सुन रहा है और नीतीश आपके मार्गदर्शक हैं।

इस रणनीति के परिणाम चुनावों में साफ दिखे हैं। 2010 से लगातार बिहार में महिलाएं पुरुषों से अधिक संख्या में मतदान कर रही हैं। 2015 के विधानसभा चुनावों में महिला-पुरुष वोटिंग का अंतर लगभग 4 तक पहुंच गया। 2020 में भी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए, बड़ी संख्या में मतदान कर किंगमेकर की भूमिका निभाई। ग्रामीण बिहार में मतदान के दिन महिलाओं की लंबी कतारें अब एक स्थायी तस्वीर बन गई हैं।

- **7 सितम्बर को घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में हर घर की एक महिला को सरकार अपना काम शुरू करने के लिए दस हजार रु. देगी और 6 माह बाद अगर उसके काम में बेहतर संभावनाएं नज़र आती हैं तो सरकार 2 लाख रु. निवेश करेगी। इस योजना के कारण बिहार की राजनीति में खलबली सी मच गई है।**
- **सवाल यह है कि क्या यह योजना वोट अधिकार की विपक्षी मुहिम को फीका कर देगी।**

ये आंकड़े महिला-केन्द्रित कल्याणकारी योजनाओं के साथ नीतीश के निरन्तर जुड़ाव को दर्शाते हैं। जब अन्य राजनीतिक दल कभी जातिवाद, कभी लोकलुभावन वादों में उलझे रहे, नीतीश ने एक स्थायी महिला-आधारित समर्थन वर्ग तैयार किया, जो राजनीतिक तूफानों में भी उनके साथ खड़ा रहा। उन्होंने गठबंधन भले ही बदले हों, भाजपा का साथ छोड़कर, आर जे डी तथा कांग्रेस के गठबंधन में चले गये हों, या फिर भाजपा के साथ आ गये हों, लेकिन उनकी महिला-केन्द्रित नीतियां निरन्तर जारी रही हैं।

2005 से लेकर 2025 तक, बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमती रही है तथा वे एक साथ, राजनीतिक उत्तरजीवी, रणनीतिकार और स्थिरता का प्रतीक बने रहे हैं।

2005, 2010, 2015, और 2020 हर विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व वाली गठबंधन की ही सरकार बना है।

2009, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी नीतीश ने एनडीए को बड़ी जीत दिलाई-2009 में 40 में से 32 सीटें, 2019 में 39 सीटें तथा 2024 में 30 सीटें।

2014 का चुनाव छोड़ दें, जब जे डी (यू) ने अकेले लड़कर सिर्फ 2 सीटें जीतीं, लेकिन तब भी 16.04 उसने वोट शेयर हासिल किया। 2020 में जे डी यू केवल 43 विधानसभा सीटें जीत सका था, लेकिन उसका असली जनाधार यथावत बना रहा था।

यह स्थायित्व बताता है कि नीतीश का समर्थन -आधार मुश्किल दौर में भी आसानी से कम नहीं होता। भाजपा के लिए नीतीश सिर्फ बैकअप नहीं, बल्कि एक "फोर्स मल्टीप्लायर" हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908